कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
DEPARTMENT OF
PERSONNEL & TRAINING
सत्यमेव जयते

ई-एचआरएमएस

इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली

मानव संसाधन प्रबंधन के लिए एक डिजिटल मार्ग

PwC

माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक) डॉ. जितेन्द्र सिंह द्वारा 25 दिसम्बर, 2017 को ई-एचआरएमएस का शुभारंभ किया गया था।

डीओपीटी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने डिजीटल कार्य परिवेश को सुविधाजनक बनाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए ई-एचआरएमएस की शुरूआत की थी।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ई-एचआरएमएस की डिजाइनिंग, विकास और कार्यान्वयन के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तकनीकी सहयोगी है।

ई-एचआरएमएस के माध्यम से सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से संबंधित सूचनाओं तक सुगमता से पहुंच बना रहे हैं। इसके माध्यम से भारत सरकार में मानव संसाधन प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप प्रदान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को बहुत-से लाभ हुए हैं और कार्यकुशलता में भी बढ़ोतरी हुई है।

ई-एचआरएमएस नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रशासन के लिए विश्लेषण सुविधा प्रदान करेगा।

ई-एचआरएमएस की विशेषताएं

- विश्वसनीय आंकड़ों का एकल स्रोत
- 24X7 पहुंच और उपलब्धता की सुविधा
- मानव संसाधन दस्तावेजों का साझा संग्रह
- भागीदारों के साथ सूचनाओं का निर्बाध साझाकरण
- एमआईएस रिपोर्टों की विश्लेषण प्रणाली
- ई-हस्ताक्षर सुविधा
- मास्टर डाटा का मानकीकरण
- अलर्ट/नोटिफिकेशन की सुविधा
- आंकड़ों की निम्नतम मैनुअल एंट्री
- पीएफएमएस, ई-ऑफिस आदि जैसे अन्य एप्लीकेशन के साथ एकीकरण

पृष्ठभूमि

व्यय प्रबंधन आयोग (ईएमसी) ने एक निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत सरकार के सभी कार्यालयों में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) स्थापित करने की सिफारिश की थी। कार्मिक प्रशासन के निष्पादन की मैनुअल प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना था।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को एनआईसी के सहयोग और संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों के सहयोग से समयबद्ध तरीके से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के संबंध में ई-सर्विस बुक के कार्य को तेजी से शुरू करने का काम सौंपा गया था।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में एक पायलट परियोजना के रूप में ई-सेवा बुक मॉड्यूल को शुरू करने का भी प्रस्ताव किया गया था।

ई-एचआरएमएस का विकास और कार्यान्वयन उच्च स्तरीय निगरानी में पूरा किया गया था।

परियोजना

कार्य- प्रणाली

ई-एचआरएमएस की सभी कार्यप्रणालियों को मॉड्यूल में वर्गीकृत किया गया है और इन मॉड्यूल को चरणों में विकसित और कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में ई-एचआरएमएस में 8 मॉड्यूल क्रियाशील हैं।

ई-एचआरएमएस के मॉड्यूल

★ *वर्तमान में क्रियाशील मॉड्यूल*

ई-एचआरएमएस संबंधी आंकड़े

दिल्ली में प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों में भारत सरकार के लक्षित कर्मचारियों की संख्या 32,000 है।

भारत सरकार के 65 मंत्रालय/विभाग शामिल

भारत सरकार के 25,000 कर्मचारियों को सफलतापूर्वक शामिल किया गया।

उच्चतम स्तर पर पर्यवेक्षण के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में ई-एचआरएमएस में 50 गुना बढ़ोतरी हासिल की गई।

भविष्य में डाक, रेलवे, रक्षा, राजस्व आदि जैसे मंत्रालयों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है

अन्य विवरण

उपयोग

आज तक लगभग 8 लाख से अधिक उपयोग सत्र (सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा ई-एचआरएमएस में लॉग इन किये जाने की संख्या) की संख्या दर्ज की गई है।

सेवा रिकॉर्ड डिजीटलीकरण

अकेले ई-एचआरएमएस केंद्र में ही कैडर कर्मचारियों के लगभग 17,500+ सेवा रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया गया है।

मॉड्यूलों का विकास

8 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं जबकि अन्य मॉड्यूल जैसे [पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस), सीजीएचएस (स्वास्थ्य योजना) और एपीएआर (वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन) एनआईसी द्वारा विकसित किए जा रहे हैं।

मंत्रालयों के लिए प्रशिक्षण

उन मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों, प्रशासन और डेटा एंट्री करमचारी के लिए प्रशिक्षण सत्र, नियमित आधार पर आयोजित किए जाते हैं जहां ई-एचआरएमएस लागू किया गया है।

अवसंरचना

ई-एचआरएमएस केंद्र को एक केंद्रीकृत सुविधा केंद्र के रूप में आईएसटीएम लाइब्रेरी ब्लॉक, पहली मंजिल, पुराना जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली में स्थापित किया गया था।

ई-एचआरएमएस सेंटर में 50 कंप्यूटर सिस्टम, 13 टेलीफोन लाइन और 35 इंटरनेट कनेक्शन के हार्डवेयर सफलतापूर्वक स्थापित किए गए थे।

ई-एचआरएमएस के विकास और सुविधाकरण के लिए एनआईसी द्वारा 30 व्यक्तियों की एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम और 45 व्यक्तियों की रोल-आउट टीम भी गठित की गई है।

ई-एचआरएमएस ऑपरेशन और रखरखाव में विशेषज्ञता रखने वाले 48 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स (डीईओ) का कुशल जनशक्ति भंडार विकसित किया गया है।

इन डीईओ को अब मॉड्यूल और सेवाओं के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों / विभागों में तैनात किया गया है।

डैशबोर्ड

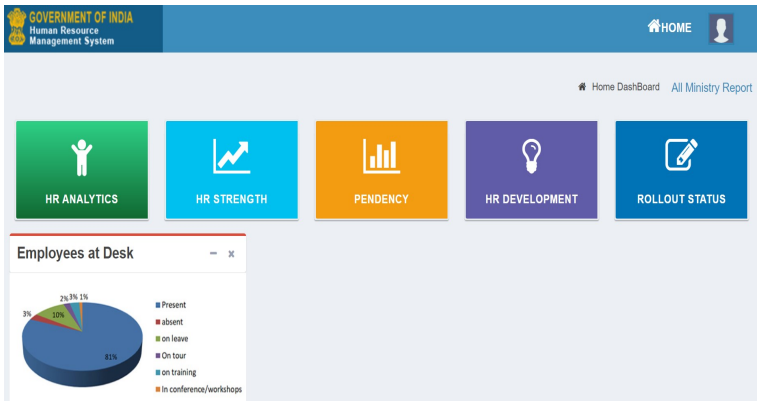

निर्णय और नीति निर्माण के लिए वरिष्ठ प्रशासन को विभिन्न विश्लेषण प्रदान करते हुए एक व्यापक ई-एचआरएमएस डैशबोर्ड विकसित किया गया है।

प्रक्रिया

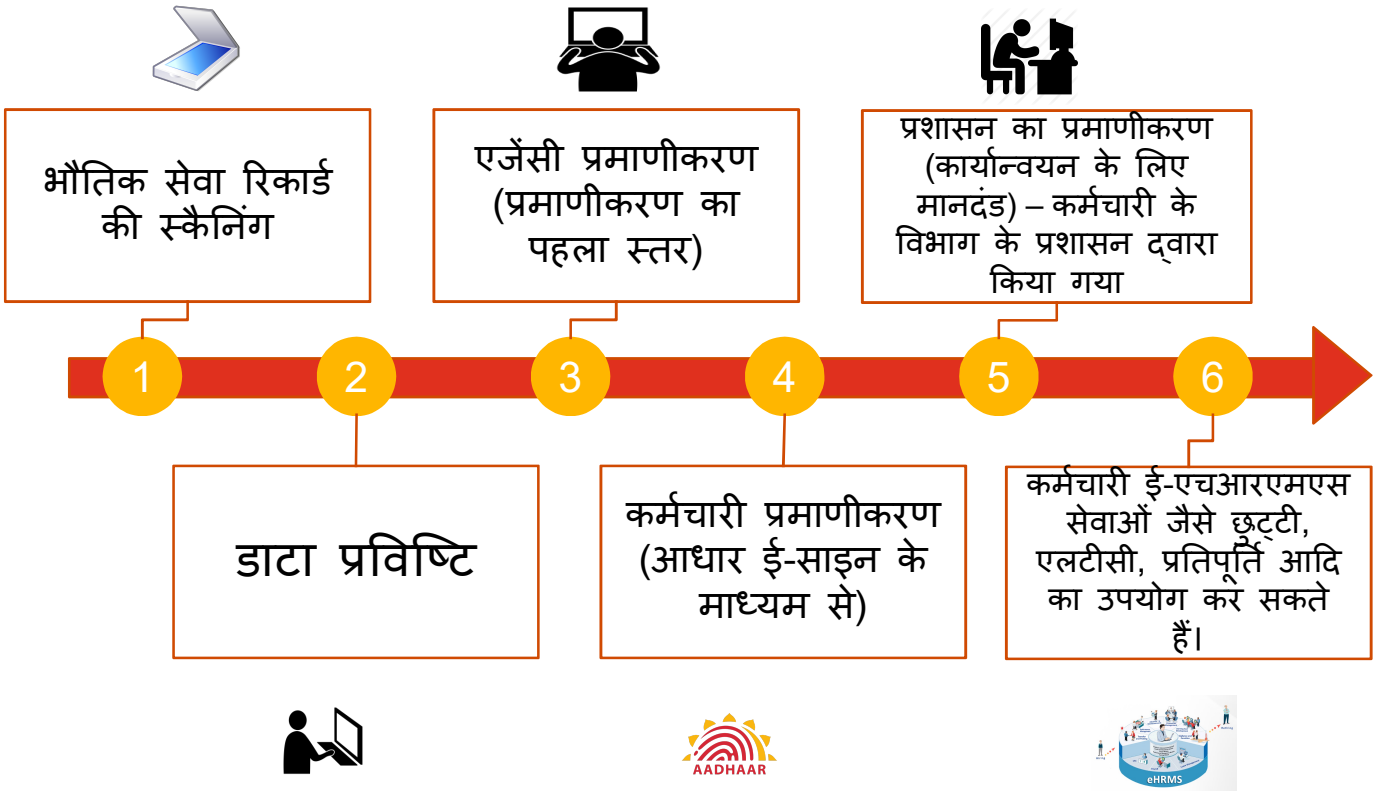

ई-एचआरएमएस का प्रसार

ई-एचआरएमएस का अनेक संगठनों / राज्यों में तेजी से कार्यान्वयन किया जा रहा है। उनमें से कुछ (कर्मचारियों की लगभग संख्या सहित) निम्नलिखित हैं:-

भारत का उच्चतम न्यायालय (2,000)

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय (1,000)

DELHI POLICE

दिल्ली पुलिस (80,000)

आईसीएआर (20,000)

एनडीएमसी (16,000)

डीडीए (6,000)

सीबीएसई (2,000)

मध्य प्रदेश सरकार (4,00,000)

महाराष्ट्र सरकार (5,00,000)

महाराष्ट्र शासन

लाभ

भारत स्वयं में एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में कागज पर पत्रों को लिखना और भौतिक फाइलों को चलाना अब अतीत की बात होनी चाहिए। पारम्परिक दस्ती कार्यालयी प्रक्रियाओं से कागज, संसाधन, समय और धन की बरबादी होती है।

मानव संसाधन प्रक्रियाओं जैसे छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी), सेवा संबंधी अभिलेखों आदि का डिजिटल रूप से प्रबंधन शुरू करके सरकार के कर्मचारियों को अधिक कुशल और दक्ष बनाया जा सकता है। इस व्यवस्था के द्वारा सरकारी मानव संसाधनों का डिजिटल रूप से प्रबंधन किया जा सकता है। अब कर्मचारी बटन पर क्लिक कर मानव संसाधन सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

यह सरकारी कर्मचारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' को सुविधाजनक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा, जो अब नई सामान्य स्थिति है।

आगे चलकर, यह ई-एचआरएमएस राज्य सरकारों और अन्य सरकारी इकाईयों द्वारा अपनाया जा सकता है जिससे सरकारी कर्मचारियों को नियोजन-से-सेवानिवृत्ति (हाइरिंग-टू-रिटायरिंग) तक के लिए सिंगल विंडो की पहुंच प्रदान की जा सकेगी।

सरकारी वित्त पर प्रभाव	यदि मान लिया जाए कि किसी कर्मचारी द्वारा सभी मानव संसाधन गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए वर्तमान में एक वर्ष में औसतन दो दिन खर्च किया जाता है (जिसे ऑटोमेशन के कारण बचाया जा सकेगा), तो हम इतने कार्य दिवसों की बचत कर सकते हैं, जो वार्षिक रूप से 30 लाख कर्मचारियों से अधिक के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए (औसत दैनिक वेतन 1000/-रू. मानने पर) के समतुल्य है।
स्वचालित निकासियां	ई-एचआरएमएस **स्वचालित निकासियों** का सृजन कर सकती है। स्वचालित निकासियों को लागू किए जाने से प्रशासन और कर्मचारी दोनों के लिए समय, धन और प्रयासों संबंधी संसाधनों की बचत होगी। इससे अंतिम उपयोगकर्ता को भी लाभ होगा जहां लोक सेवाएं प्रदान करना मंत्रालय/विभाग का मुख्य कार्य है।
सेवानिवृतियां	ई-एचआरएमएस विभिन्न कार्यालयों/अनुभागों से विभिन्न आवेदन पत्रों(जैसे अनापत्ति प्रमाण पत्र, बेबाकी प्रमाण पत्र आदि) को भरने के लिए कर्मचारियों के खर्च होने वाले समय को समाप्त करेगा जिससे सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् **जीवन सुगमता (ईज ऑफ लिविंग)** का अनुभव मिलेगा।
सीखना और सीखने से संबंधित अभिलेखों का प्रबंधन	**आई-गॉट कर्मयोगी** (कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल) के साथ एकीकरण पदाधिकारियों के सीखने से संबंधित अभिलेखों के डिजिटाईजेशन को सक्षम बनाएगा।

ई-एचआरएमएस और मिशन कर्मयोगी

सरकार ने एक ऐसी पेशेवर, सुप्रशिक्षित और भविष्योन्मुखी सिविल सेवा का सृजन करने के लिए मिशन कर्मयोगी, राष्ट्रीय सिविल सेवा दक्षता विकास कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) शुरू किया है, जो भारत की विकासात्मक आकांक्षाओं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं की साझी समझ से गहराई से जुड़ी हो।

कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों में सही दक्षताओं को विकसित करना है ताकि वे अपनी भूमिका का सर्वोत्तम रूप से निर्वहन कर सकें। एनपीसीएससीबी का प्रमुख दर्शन 'नियम-आधारित' प्रणाली से 'भूमिका-आधारित' प्रणाली में परिवर्तन के माध्यम से एक दक्षता संचालित प्रशिक्षण और मानव संसाधन (एचआर) प्रबंधन कार्यतंत्र का सृजन करना है।

मिशन कर्मयोगी की परिकल्पना नीचे दिए गए छह-स्तंभों पर की गई है। यह मिशन मानव संसाधन पर मुख्य जोर देता है इसलिए ई-एचआरएमएस स्वयं इसके मुख्य स्तंभों में से एक है।

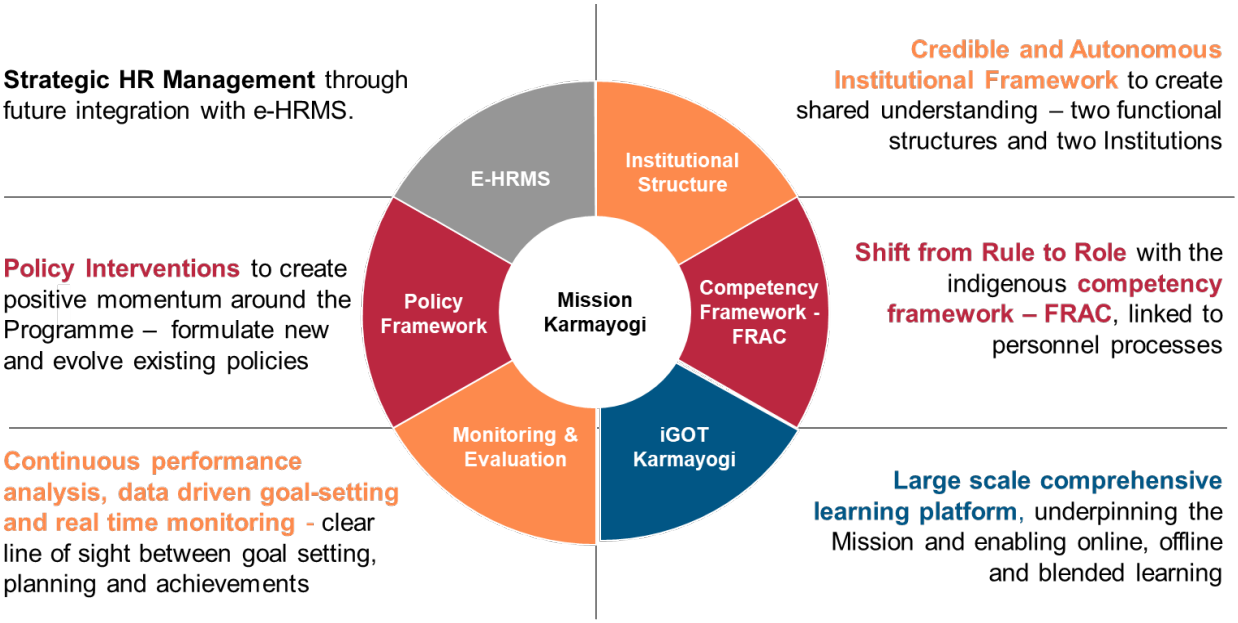

मिशन कर्मयोगी के छः मुख्य स्तम्भ

दीर्घावधि में क्षमता विकास प्लेटफॉर्म को ई-एचआरएमएस के साथ एकीकृत करने की आकांक्षा है। यह न केवल सेवा और मानव संसाधन संबंधी मामलों के डिजिटल प्रबंधन को सक्षम बनाएगा बल्कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सही समझ प्रदान करेगा कि सही व्यक्ति को सही काम पर तैनात किया जाए।

भावी योजनाएं

विभिन्न प्लेटफार्म एकीकरण किए जाने के लिए तैयार हैं। ई-एचआरएमएस के साथ संभावित एकीकरण के लिए तीन एप्लीकेशन-सुप्रीमों (ऑनलाइन कर्मचारियों से संबंधित एकल उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म), स्पैरो (वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन), वीआईएस (सतर्कता सूचना प्रणाली) की पहचान की गई है।

यदि इसे ब्रांड के रूप में विकसित किया जाता है और मित्र देशों के साथ इसका विपणन किया जाता है, तो ई-एचआरएमएस में भारत सरकार के लिए राजस्व सृजन की क्षमता है। यह भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकता है और सार्वजनिक मानव संसाधन प्रबंधन में भारत के नेतृत्व को सुदृढ़ कर सकता है।

सत्यमेव जयते

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

DEPARTMENT OF

PERSONNEL & TRAINING

PwC